REGISTERED No. D. 221



ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3 ---- उपसण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86]

नई विल्ली, बृहस्पितवार, मई 13, 1971/बैशाल 23, 1893

No. 86]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 1971/VAISAKHA 23, 1893

इस भाग में भिश्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह झलग संकलन के कप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May 1971

G.S.R. 691.—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas I, V. V. Giri, President of India, have received a report from the Governor of the State of Gujarat and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I-

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:
 - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State; articles 163 and 164;
 - so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; articles 167 and 169; clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive); clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;
 - so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 189, 193, 194, 195 and 196; article 198; clauses (3) and (4) of article 199; articles 200 and 201;
 - so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
 - so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
- (iii) the Logislative Assembly of the said State is hereby dissolved;
- (iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:
 - Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;
- v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Bombay General Clauses Act, 1904, (Bombay Act I of 1904) as in force in the State of Gujarat and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI; The 13th May, 1971. V. V. GIRI,

President.

[No. 38/12/71-Poll. I(A).] GOVIND NARAIN, Secy.

NEW DELHI; The 13th May, 1971.

गृह मंत्रालय

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 1971

जी०एस०भ्रार० 691.—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वेसाधारण के सूचनार्थ प्रकाणित की जा रही हैं :——

यत : मुझे, व० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपित को गुजरात राज्य के राज्यपाल से एँक रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा उस रिपोर्ट पर भ्रौर मुझे प्राप्त भ्रन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपधन्धों के श्रनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

श्रतः श्रव मैं, संविधान के श्रनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थं बनाने वाली श्रन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं:--

- (क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य श्रीर उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्ब्रारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रपने हाथ में लेता हुं।
- (ख) धोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंजल की शक्तिया संसद के प्राधिकार द्वारा या ग्रधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; श्रौर
- (ग) निम्निलिखित ग्रानुषंगिक ग्रौर पारिणामिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्दश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझ ग्रावश्यक या बांछनीय प्रतीत होते हैं, ग्रायात्:—
 - (i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के श्राधार पर श्रपने हाथ में लिए गए कृत्यों श्रौर शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रप ति के रूप म उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

- (ii) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्शन को
 एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, प्रर्थात् :—
 - अनुच्छोद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निवेश करने से है ;

प्रनुष्ठेद 163 घीर 164 ;

श्रनुष्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के बीच श्रावंटन से हैं ;

श्रन् च्**छद** 167 श्रीर 169 ;

- श्रनुष्ठव 174 का खंड (1) श्रीर खंड (2) का उपखंड (क) ; श्रनुष्ठव 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ; श्रनुष्ठेद 179 का खंड (ख) श्रीर (ग) श्रीर उस श्रनुष्ठेद का प्रथम परन्तुक श्रीर श्रनुष्ठेद 180 श्रीर 181 ;
- भ्रनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्बन्धों भ्रौर मतों से हैं ; भ्रनुच्छद 189, 193, 194, 195 तथा 196 ; भ्रनुच्छद 193 ; भ्रनुच्छेद 199 का खंड (3) भीर खंड (4) श्रनुच्छद 200 भीर 201 ;
- श्रनुष्छद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपा-ध्यक्ष के सम्बन्धों श्रौर भतों से है; श्रनुष्छद 208 से 211 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं); श्रनुष्छद 213 के खंड (1) का परन्तुक श्रौर खंड (3) का परन्तुक; श्रौर
- अनुच्छद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;
- (iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्शारा विषटित की जाती है;

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का श्रर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा श्रीर उसमें राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके शृत्यों श्रीर उसकी शक्तियों से है, श्रथं जब तक कि सन्दर्भ में भ्रन्यथा श्रपे-क्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा, श्रीर विशिष्टतया भन-च्छेद 213 में राज्यपाल श्रीर राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निदेश का श्रथं कमश: राष्ट्रपति श्रीर संसद् या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें की कोई बात अनु च्छेद 153, अनु च्छेद 155 से लेकर अनु च्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) अनु च्छेद 299 और अनु च्छेद 361 तथा ब्रितीय अनु सूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपख्या (1) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझें, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(v) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्द्वारा बनाए गए श्रिधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐ से अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके श्रन्त-गंत इस उद्घोषणा के ग्राधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्ररित या संविधान के श्रनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट श्रन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बनाए गए श्रिधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, भौर बम्बई साधारण खण्ड श्रिधिनियम, 1904, (बम्बई 1904 का श्रिधिनियम 1) जिस रूप में गजरात राज्य में लाग हैं और साधारण खण्ड श्रिधिनियम 1897 (1897 के 10 व) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी श्रिधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मंडल का श्रिधिनियम ।

न**ई** दिल्ली, 13 मई, 1971

व० वे० गिरि, राष्ट्रपति ।

[संख्या 38 / 12 / 71 नांसि 1 (ए)]

गोबिन्द नारामण, सचिव।

नई दिल्ली, 13 मई, 1971

ORDER

New Delhi, the 13th May 1971

G.S.R. 692.—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 13th day of May, 1971, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Gujarat and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI:

V. V. GIRI,

The 13th May, 1971.

President.

[No. 38/12/71-Poll.I(A).]

NEW DELHI;

GOVIND NARAIN, Secy.

The 13th May, 1971.

मा देश

नई दिल्ली, 13 मई, 1971

् जी० एस० भार० 692.--राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित श्रादेश सर्वेसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1971 को मई के 13 वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि गुजरात राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रकृत किसी विधि के प्रधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोक₁व्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ण उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के ग्राधार पर भ्रपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के श्रधीक्षण, निदेशन ग्रौर नियन्त्रण के ग्रध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक₁व्य होंगी ।

नई दिल्ली,

व० वे० गिरि,

13 मई, 1971

राष्ट्रपति ।

[मं० 38/12/71पोहो० 1 (ए).]

नई, दिल्ली,

गोविन्द नारायण, सिचव ।

13 मई, 1971